

# Amolakchand Mahavidyalaya, Yavatmal.

## A REPORT

### On

### Seminar on National Education Policy-2020

One-day seminar on the National Education Policy-2020 was organized on 24<sup>th</sup> April 2022. The event, organized by the Internal Quality Assurance Cell, aimed to delve into the various facets of the National Education-2020.

The resource persons, Dr. Pravin Raghuvanshi, Professor in Chemistry, Shri. Brijlal Biyani College, Amravati and Dr. Mahendra Mete, Librarian, Shri Shivaji Science College, Amravati offered valuable insights into the National Education Policy-2020, addressing both its merits and identified loopholes. The discussions covered diverse aspects, providing a comprehensive understanding of the policy's implications on the education landscape as, key provisions and implications of the National Education Policy-2020, potential drawbacks and areas needing refinement within the policy framework, and its impact on educational institutes.

The seminar witnessed active participation from faculties of Amolakchand Mahavidyalaya and other institutions within the district. A total of 300 participants engaged in the dialogue, fostering an enriching exchange of ideas and perspectives.

Dr. R. A. Mishra, Principal of Amolakchand Mahavidyalaya, was the organizer, and Prof. D. S. Chavhan, IQAC Co-ordinator, served as the Convener.

The seminar on the National Education Policy 2020 facilitated a robust exchange of ideas, fostering a deeper understanding of the policy's nuances. The active participation of 300 attendees, including educators from various institutions, exemplifies the significance of such events in shaping informed perspectives on crucial educational reforms.

**स्वदेश**

दि. २७/४/२०२२

नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचे यश हे योग्य अंमलबजावणी वरच : डॉ. प्रवीण रघुवंशी



अमोलकचंद महाविद्यालय येथे आयोजित परिसंवादात उपस्थित असलेले मान्यवर कार्यक्रमाचे अध्यक्ष प्राचार्य डॉ. राममनोहर मिश्रा, डॉ. प्रवीण रघुवंशी, डॉ. मेटे, प्रा.डॉ. डी.एस. चव्हाण आणि प्रा. जाधव.

# राष्ट्रीय शिक्षा नीति की चुनौतियों को समझें : रघुवंशी

• चर्चासत्र में छात्र, प्राध्यापक व व्यवस्थापन से किया आह्वान

संवाददाता | यवतमनगर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर अमल करने के लिए चुनौतियाँ, छात्र अध्यापक और व्यवस्थापन आदि संगठनकार लें अन्वया शिक्षा क्षेत्र में विकसित होना, ऐसे विचार नुस्ते के अन्वय डॉ. प्रवीण रघुवंशी ने व्यक्त किए। वह स्थानीय अमोलकचंद महाविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर चर्चा में बोल रहे थे। समावेश की अवधारणा प्रचारार्थ यममननगर विद्या में की। डॉ. रघुवंशी ने कहा कि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने देश में आईआईटी जैसे संस्थाएँ स्थापित कर देश के लिए उससे शिक्षा नीति कायमिन्वित की थी। बाद में डा. राधाकृष्णन ने आज़ादी के बाद उच्च शिक्षा नीति तय की। जिसमें देश को एक दिशा मिली। कोट्यारी आयोग ने जीडीपी के 6 फीसदी राशि शिक्षा पर खर्च करने को सलाह दी। यही नहीं विभागीय नीति स्वीकार कर शिक्षा प्रादेशिक भाषा से देने का आग्रह किया। 1986 में नई शिक्षा नीति में देश के मेधावी छात्रों के लिए नवोदय विद्यालय शुरू किए। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड, विद्यार्थी केंद्रित योजनाएँ शुरू कीं। 1992 में डरम में सुधार कर देश के हर शिक्षा नीति और शिक्षा जेडीपी पर 6 फीसदी खर्च की शिफारिस की गई। एमर एक भी सरकार ने इनका खर्च शिक्षा पर नहीं किया। डा.रघुवंशी ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के काल में वैदिक



शिक्षा देने वाले संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित हुए, फलस्वरूपीय जैसे विषय पाठ्यक्रम में आए। 2002 को विश्व-अभिवृत्ति समिति ने उच्चशिक्षा का पूरा निरीक्षण करने की शिफारस की। नई शिक्षा नीति, छात्र, प्राध्यापक, व्यवस्थापन के सामने चुनौती है। डा. मिश्रा ने नई शिक्षा नीति का जयजय लिया। इस अवसर पर डा. रघुवंशी का महाराष्ट्र प्राध्यापक महासंघ के महासचिव पद पर चयन होने पर उनका सत्कार किया गया। संयोजक प्रा. किशोर बुटले, प्रसाधना डा. डी एस चव्हाण और आभार डा. आर बी भांडवलकर ने माना।

**3 हजार से कम विद्यार्थियों वाले महाविद्यालय होंगे बंद** : 2030 तक हर महाविद्यालय को होलबीकरणा करना कर उन्हें सहायता देने की शिफारिस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में की है। 3 हजार से ज्यादा छात्र वाले महाविद्यालय बंद कर अन्य शिक्षा संस्थाओं में उन्हें शामिल किया जाएगा।

जिससे व्यवस्थापन के सामने बड़ी समस्या निर्माण हो सकती है। इससे छात्रों के बाहर जाने से शिक्षाओं उच्च शिक्षा में परिणत हो सकती हैं।

**ऑनलाइन शिक्षा से अध्यापकों की नौकरी खतरे में** : अमोलकचंद शिक्षा तटीका, क्रेडिट सिस्टम से अध्यापकों के पद बड़े पैमाने पर घटने वाले हैं। जिससे अध्यापकों के सामने भी बड़ी चुनौती निर्माण होगी। बैंक धोखाधड़ी से अर्थव्यवस्था खतरे में आई है।

**राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए 2 वर्ष से बजट में कोई प्रावधान नहीं** : राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत केवल केवल के 2 वर्ष पूरे होने के बावजूद कहीं पर भी बजट में प्रावधान नहीं किया गया। जिससे शिक्षा नीति पर सार्वजनिक विरोध लगा जाए है। जब बजट ही नहीं तो उस पर काम करने का प्रयास देश सरकारें शुरू कर रही हैं। शैक्षणिक नीति में सुधार का विद्यार्थी संघर्ष भी शामिल नहीं हो पा रहा है।

**नई पेंशन नीति षडयंत्र** : नई पेंशन नीति पर चलने समय डा.महेंद्र मेटे ने शिक्षा व्यवस्था और अध्यापकों को आने वाले दिक्कतों के बारे में विचार उठे। नई पेंशन योजना अध्यापक और कर्मचारियों की कुटुंबों पर पड़ने वाली बोझ को अतीत करण है। इस दुःख के कारण नई परिवर्तन का उद्देश्य है। आगे चलने की बात बनाई गई पेंशन योजना एक षडयंत्र होने का आरोप भी किया।

## अंमलबजावणी अभावी नवीन शिक्षण धोरण विध्वंस घडविणारे - डॉ प्रवीण रघुवंशी

बँक घोटाळ्यामुळे अर्थव्यवस्था धोक्यात-डॉ महेंद्र मेटे, अमोलकचंद महाविद्यालयात आयोजित चर्चासत्रात सूर

वाशिम संदेश, यवतमन

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण अमलबजावणी समोर्ण आहूणे विद्यार्थी, शिक्षक, व्यवस्थापन समूह व्यापी,अन्वया शिक्षण क्षेत्रात विध्वंस घडते, असे प्रतिपादन नुस्ते अन्वय डॉ.प्रवीण रघुवंशी यानी केले. स्थानिक अमोलकचंद महाविद्यालय 'राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020' या विषयावर आयोजित चर्चासत्रात ते बोलत होते. प्राचार्य डॉ राममनोहर मिश्रा यांच्या अध्यक्षते प्रारंभित चर्चासत्रात धोरणातना डॉ. रघुवंशी म्हणाले की, देशाचे प्रथम प्रथम मंत्री पंडित जवाहरलाल यांनी देशात आय.आय.टी सारख्या संस्था स्थापन करून देशात अग्रिम अस्तित्वे शैक्षणिक धोरण राबविले. डॉ. राधाकृष्णन यांनी स्वातंत्र्य नंतर उच्च शिक्षणाचे धोरण ठरविले व देशात एक दिशा दिती.कोट्यारी आयोगने 6 टक्के खर्च शिक्षणावर द्यावा असे सुचविले व त्री भाषा धोरण स्वोकाशन शिक्षा प्रादेशिक भाषांनु देण्याचा आग्रह परना. रात्री



गांधी यानी 1986 साली नवीन शैक्षणिक धोरण आणले व प्राचीन भागातील गुणवत्ता विद्यार्थ्यांसठी नवोदय विद्यालये सुरू केलेत. ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड, विद्यार्थी केंद्रित योजना सुरू केल्या. त्यात 1992 मध्ये सुधारणा सुचविण्यात आल्या. देशातील प्रत्येक शैक्षणिक धोरण शिक्षणावर 6 टक्के खर्चाची शिफारस करते परंतु एकाही सरकारने शिक्षणावर अनेकित खर्च केला नाही. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या काळात वैदिक शिक्षण देणारी संस्कृत विद्यापीठे स्थापन झाली व फलस्वरूपीय सारखी विषय

अप्यसक्रमात आले.2002 साली बिली अंभवी समितीने उच्च शिक्षणाची संपूर्ण खाकणीकरण करण्याची शिफारस केली, असा भारतीय शिक्षणाचा धोरणाचा आढावा घेऊन डॉ.प्रवीण रघुवंशी यानी नवीन शैक्षणिक धोरणामुळे विद्यार्थी,अध्यापक व व्यवस्थापन यांचे समोर पैशाच्या आव्हानाची चर्चा केली. सन 2030 पर्यंत प्रत्येक महाविद्यालयाचे सार्वजनिककरण संसृष्टात आणून त्यांना स्वायत्तता देण्याची शिफारस राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाने केली असून 3000 विद्यार्थी संख्या पेक्षा कमी असलेली महाविद्यालय बंद होऊन

इतर शिक्षण संस्था मध्ये त्यांचे विलीन होईल. त्यामुळे व्यवस्थापनासमोर मोठी समस्या निर्माण होवू शकते. मल्टिपल एम्प्लॉयमेंट बँच विद्यार्थी उच्च शिक्षणासमूर संघित राहतील. ऑनलाईन शिक्षण पद्धत, क्रेडिट सिस्टीम यांमुळे शिक्षकांची परे प्रचंड प्रमाणात घटतील व त्यामुळे शिक्षकांसमोर मेटे आव्हान निर्माण होईल, बँक घोटाळ्यामुळे अर्थव्यवस्था धोक्यात आली आहे असे मत त्यांनी व्यक्त केले. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण केड सरकारने स्वोकारल्यासमूर देण खर्च झाली परंतु कुटुंबीही अंतःकवत्रीय

तराट झाली नसल्याने धोरणावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते.समूह शैक्षणिक धोरणामध्ये सुचविलेले नियामक मंडळ मुद्रा स्थान झाले नसल्याचे त्यांनी सांगितले. तर नवीन पेंशन धोरणावर बोलतांना डॉ महेंद्र मेटे यांनी शिक्षण व्यवस्था व शिक्षकांना पैशाच्या अडचणीबाबत महत्त्वपूर्ण प्रतिपादन केले. नवीन पेंशन योजना शिक्षक व कर्मचारी यांची सुरक्षा संविधानात अमल्याचे म्हटले. त्यांनी पेंशन ला संविधान व कायद्याचा आधार असल्याचे सांगितले. गौडा सार धोरणात शोधने केले जात असून हे धोरण समतुल्य ध्यायसा होवे, असे ते म्हणाले चर्चासत्राचे अन्वय डॉ मिश्रा यांनी नवीन शिक्षण धोरणाचा संविधान आढावा घेताना महाराष्ट्र प्राध्यापक महासंघाच्या महासचिव पदी निवड झाल्याबद्दल डॉ.प्रवीण रघुवंशी यांचा सात्कार करण्यत आला.कार्यक्रमाचे संयोजक महाविद्यालयाचे यानी केले. कार्यक्रमाचे संवाहन प्रा किशोर बुटले, प्रसाधिक डॉ. डी एस चव्हाण, व आभार प्रदर्शन डॉ आर बी भांडवलकर यांनी केले.







Vidya Prasarak Mandal's  
**AMOLAKCHAND MAHAVIDYALAYA,  
YAVATMAL**

**One Day Seminar on**  
**National Education Policy 2020**

## Certificate

This is to certify that Mrs./Dr. Madhuri W. Bhade  
of Amolakchand Mahavidyalaya, Yavatmal has participated in One Day Seminar  
on "National Education Policy 2020" conducted on 24 April 2022.

  
Prof. D. S. Chavhan  
Convener & IQAC Co-ordinator,  
Amolakchand Mahavidyalaya, Yavatmal

  
Dr. R. A. Mishra  
Chairperson & Principal,  
Amolakchand Mahavidyalaya, Yavatmal